

सारणी 51.2 : सातवीं पंचवर्षीय योजना में संसाधनों का क्षेत्रवार आबंटन

(करोड़ रुपये)

क्रम	क्षेत्र	योजना परिव्यय	कुल का प्रतिशत	वास्तविक व्यय	कुल का प्रतिशत
1.	कृषि	10,574	5.9	12,793	5.8
2.	ग्रामीण विकास	9,074	5.0	15,247	7.0
3.	विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम	3,145	1.7	3,470	1.6
4.	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण	16,979	9.4	16,590	7.6
5.	ऊर्जा	54,821	30.5	61,689	28.2
6.	उद्योग व खनन	22,461	12.3	29,220	13.4
7.	परिवहन	22,971	12.8	29,548	13.5
8.	संचार, सूचना व प्रसारण	6,472	3.6	8,426	3.9
9.	विज्ञान व प्रौद्योगिकी	2,466	1.4	3,024	1.4
10.	सामाजिक सेवाएं	29,350	16.3	34,960	15.9
11.	अन्य	1,687	0.9	3,763	1.7
	कुल	1,80,000	100.0	2,18,730	100.0

स्त्रोत : *Seventh Five Year Plan, 1985-90, Volume I, p. 27, Table 3.4(a)* ; and *Economic Survey 1992-93, Table 2.6A and 2.6B, pp. 46-7.*

जैसाकि इस सारणी से स्पष्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित व्यय 1,80,000 करोड़ रुपए था। सबसे अधिक संसाधन ऊर्जा क्षेत्र के लिए रखे गए। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 54,821 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया तो कुल परिव्यय का 30.5 प्रतिशत था। वास्तविक व्यय इससे कुछ कम रहा (प्रतिशत के रूप में)। कृषि, ग्रामीण विकास, विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रमों तथा सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण का कुल वास्तविक व्यय में हिस्सा 22.0 प्रतिशत बैठता है (2,18,730 करोड़ रुपए में से 48,100 करोड़ रुपए)। यह संभावित था क्योंकि सातवीं योजना की विकास युक्ति में कृषि के विकास पर जोर दिया गया था। इस योजना के दौरान उद्योग क्षेत्र को केवल 13.4 प्रतिशत संसाधन उपलब्ध कराए गए जो इस बात का प्रतीक है कि विकास की नई युक्ति अब महलानबीस की विकास युक्ति से पूरी तरह दूर हो चुकी थी जिसने लगभग दो दशक तक इस देश में आयोजित विकास की दिशा का निर्धारण किया था। परिवहन क्षेत्र को भी मात्र 13.5 प्रतिशत संसाधन प्राप्त हुए जो पूर्व योजनाओं की तुलना में, प्रतिशत रूप में, कम थे। इस प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतर झुकाव ऊर्जा क्षेत्र तथा कृषि व ग्रामीण विकास की ओर था।

निवेश संसाधनों के आबंटन का जहाँ तक प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई जिनमें जल्द उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से देखें तो उन परियोजनाओं को प्राथमिकता क्रम में कम महत्व दिया गया जो सातवीं योजना के समापन के बाद ही उत्पादन दे सकती थीं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात उपलब्ध पूंजी स्टॉक की उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास थे (प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण की सहायता से)। अंततः, संसाधनों का आबंटन इस प्रकार किया गया जिससे आधुनिकीकरण क्षेत्र, अन्य उत्पादन क्षेत्रों तथा मानव संसाधन विकास क्षेत्रों में संतुलन बनाया जा सके।